बदलाव के कदम

ई-मोबिलिटी योजना लागू करने वाला प्रदेश का पहला शहर बना अपना लखनऊ

ई-व्हीकल से लैस होगा रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट का पब्लिक ट्रांसपोर्ट

अतुल भारद्वाज

लखनऊ। राजधानी जल्द ही पर्यावरण को स्वच्छ बनाने वाले ग्रीन यातायात का मॉडल बनेगा। लखनऊ प्रदेश में ई मोबिलिटी प्लान लागू करने वाला पहला शहर बन गया है। शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी ई-व्हीकल (ईवी) से लैस किया जाएगा। रेलवे, एयरपोर्ट, बस अड्डा, मेट्रो कहीं से भी आने-जाने के लिए ईवी मिल जाएगी। वहीं, कूड़ा भी ईवी ट्रकों से ही उठेगा। सभी सरकारी विभाग के अधिकारी केवल ईवी का उपयोग ही करेंगे।

राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए विस्तृत ई-मोबिलिटी योजना को बुधवार को लॉन्च कर दिया गया। इसके तहत सरकारी विभागों से लेकर होम डिलीवरी, व्यावसायिक वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक में ईवी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। लखनऊ दूसरे शहरों के लिए भी मॉडल बनेगा। प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास विभाग ने एशियन डवलपमेंट बैंक, नीति आयोग, वैश्विक विकास सलाहकार एजेंसी प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (पीडब्ल्यूसी) के सहयोग से लखनऊ के लिए विशेष तौर पर ई-मोबिलिटी योजना को तैयार कराया है। इंवेस्ट यूपी की तरफ से गोमतीनगर स्थित होटल में आयोजित न्यू उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 पर आयोजित कार्यशाला में इसे लॉन्च किया गया। लॉन्च कार्यक्रम में मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र के अलावा इंवेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश, मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब, डीएम सूर्यपाल गंगवार भी मौजूद रहे।

- ईवी की बिक्री बढ़ाने के साथ ही चार्जिंग, बैटरी स्वैपिंग को दिया जाएगा बढ़ावा
- प्रदूषण कम करने के लिए सभी प्रमुख स्थानों को ईवी से लिंक करने और सरकारी विभागों को पूरी तरह से ईवी पर लाने की योजना

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की मौजूदगी में लखनऊ का ई-मोबिलिटी प्लान लॉन्च किया गया। -संवाद

ऐसे आएगा बदलाव : नगर विकास विभाग और स्मार्ट सिटी में ई-बस की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं सरकारी विभागों को भी ईवी खरीदने या किराए पर लेने का विकल्प दिया जाएगा। चारबाग रेलवे स्टेशन, मेट्रो के सभी स्टेशन, एयरपोर्ट, आलमबाग सहित अन्य बस अड्डे भी ईवी के जरिए लिंक किए जाएंगे।

सात विभाग करेंगे एक साथ काम : इंवेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश का कहना है कि लखनऊ को प्रदेश के पहले ई-मोबिलिटी योजना वाले शहर के लिए चुना गया है। ई-मोबिलिटी योजना पर इंवेस्ट यूपी के अलावा औद्योगिक विकास विभाग, आवास विभाग , नगर विकास विभाग, स्मार्ट सिटी मिशन, यूपीनेडा, परिवहन विभाग काम कराएंगे।

सात साल में 10 गुना बिक रहे ईवी : ई-मोबिलिटी प्लान में कहा गया है कि 2015 में जहां केवल 923 ईवी ही लखनऊ में पंजीकृत हुए थे। 2022 में 10 गुना से अधिक वाहन पंजीकृत हुए। 2022 में 11265 वाहन लखनऊ में आरटीओ में पंजीकृत कराए गए। लखनऊ इसमें पूरे प्रदेश में अगुआ साबित हुआ है।

50 फीसदी कार्बन उत्सर्जन वाहनों से : शहर में कुल कार्बन उत्सर्जन का 50 फीसदी वाहनों की वजह से है। इसी तरह सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले अति सूक्ष्मकण पीएम2.5 के उत्सर्जन के आंकड़ों को देखें तो वाहनों की हिस्सेदारी 17 फीसदी है। सर्दियों में हवा इतनी खराब हो जाती है कि औसत एक्यूआई भी 290 के ऊपर पहुंच जाता है।

इन सुझावों पर होगा काम

- सरकारी विभाग लोग पर ई-व्हीकल विभागीय कार्यों में उपयोग के लिए लें, इससे लोगों में भी ईवी के लिए भरोसा बढ़ेगा।
- सॉलिड वेस्ट कलेक्शन में ईवी का उपयोग बढ़ाया जाए। इससे प्रदूषण कम होगा और सड़कों पर ईवी की अधिक संख्या दिखाई देगी।
- कॉरपोरेट कंपनियां अपने कर्मचारी, अधिकारियों के लिए ईवी का उपयोग करें। होम डिलीवरी व सर्विस जैसे व्यावसायिक कामों में भी ईवी का उपयोग हो।
- मेट्रो स्टेशनों पर ई-साइकिल, ई-बाइक के लिए स्टैंड बनाए जाएं। इनको चार्ज करने के लिए लखनऊ मेट्रो की बिजली उपयोग की अनुमति हो।
- 15 साल की उम्र पूरी करने वाले वाहनों को ट्रेक कर उनको उपयोग से हटाया जाए। ऐसे वाहन मालिकों को ईवी खरीदने में सहूलियत भी दी जाए।